प्रेस विज्ञप्ति

22 अक्टूबर, 2015

रणदीप सिंह सुरजेवाला, इन्चार्ज कम्युनिकेशंस, अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी ने आज प्रेसवार्ता में निम्नलिखित बयान जारी किया :–

"**1.** कल गृहराज्यमंत्री श्री किरन रिजुजू ने सभी उत्तर भारतीयों को अपराधी करार कर यह कहा कि उत्तर भारतीय कानून तोड़ने में गर्व महसूस करते हैं। यह संपूर्ण देश का अपमान है। बड़े दुख की बात तो यह है कि उन्होंने जब यह बयान दिया तब गृहमंत्री, श्री राजनाथ सिंह वहीं मौजूद थे, जिन्होंने इस विवादित बयान का खंडन तक नहीं किया। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस भाजपा के वरिष्ठ मंत्रियों के द्वारा बिहार से लेकर गुजरात तक के सभी उत्तर भारतीयों के इस अपमान की कड़ी निंदा करती है और हम मांग करते हैं कि श्री किरन रिजुजू अपने इस बयान के लिए माफी मांगें, नहीं तो उन्हें उनके पद से बर्खास्त किया जाए। श्री राजनाथ सिंह को भी मौन रहकर उन्हें समर्थन देने के लिए माफी मांगनी चाहिए।

मोदी सरकार के मंत्रियों का सत्ता का अहंकार सीमा लांघ गया है। भाजपा शासित मुंबई और महाराष्ट्र में बिहार और यूपी के लोगों पर हमले और नौकरियां न दिए जाने से लेकर श्री अरुण जेटली के द्वारा कलाकारों के विरोध को 'साजिशभरा विद्रोह' कहने और एनजेएसी के फैसले के खिलाफ सर्वोच्च न्यायालय के लिए शर्मनाक बयान देना, हरियाणा के मुख्यमंत्री श्री मनोहर लाल खट्टर के द्वारा नागरिकता की नई परिभाषा देने से लेकर श्री महेश शर्मा के द्वारा लड़कियों के लिए नैतिकता के नए कोड बनाए जाने तक, श्री मुख्तार अब्बास नकवी और श्री गिरिराज सिंह के द्वारा कुछ लोगों को पाकिस्तान चले जाने की सलाह देने से लेकर श्री संजीव बलियन/श्री महेश शर्मा के द्वारा हत्या की नई परिभाषा खोजने तक, साध्वी निरंजन ज्योति के द्वारा भारत की जनता के एक विशेष वर्ग को गाली दिए जाने जैसी अनेक घटनाओं से केंद्र और राज्य की भाजपा सरकार भारत में नफरत का बीज बो रही हैं।

हम मोदी सरकार के मंत्रियों के द्वारा 'प्रतिदिन एक नया विवाद' पैदा करने की नीति की कड़ी निंदा करते हैं।

2. भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस दो दलित बच्चों को आग लगाकर उनकी हत्या कर देने की निर्दयी घटना में केंद्रीय मंत्री जनरल वी. के. सिंह के विवादित व अमानवीय बयान की कड़ी निंदा करती है। जनरल वी. के. सिंह का बयान मोदी सरकार की दलित विरोधी व गरीब

विरोधी मानसिकता प्रदर्शित करता है। भाजपा और उसके मंत्रियों के बयान न केवल निंदनीय और निर्लज्ज हैं, बल्कि उन्होंने संपूर्ण देश सहित समूचे दलित समुदाय का अपमान किया है। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस मांग करती है कि अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति (अत्याचार निवारण) अधिनियम, 1989 के सेक्शन 3 और 4 के अंतर्गत केंद्रीय मंत्री जनरल वी. के. सिंह के खिलाफ तत्काल अपराधिक मुकदमा दर्ज कराया जाए। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी को न केवल जनरल सिंह को केंद्रीय मंत्रिमंडल से बर्खास्त करना चाहिए, बल्कि पूरे देश एवं संपूर्ण दलित समुदाय से मॉफी भी मांगनी चाहिए।

भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस इस बात पर चिंता व्यक्त करती है कि पिछले कुछ महीनों से भाजपा–आरएसएस सोचे समझे तरीके से दलितों और पिछड़ा वर्ग के खिलाफ वातावरण बना रही है। आरएसएस सरसंघचालक, श्री मोहन भागवत के द्वारा दलितों और पिछड़ा वर्ग को दिए जाने वाले आरक्षण की समीक्षा की मांग करने के बाद उन्होंने इसी बात को दो बार और दोहराया। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी या भाजपा अध्यक्ष श्री अमित शाह ने आज तक श्री मोहन भागवत् के बयान की निंदा क्यों नहीं की, यह भी सोचने का विषय है?

मोदी सरकार की दलित विरोधी मानसिकता केवल शर्मनाक बयानों और आरक्षण की समीक्षा की मांग तक सीमित नहीं है, बल्कि यह दलितों की कल्याण योजनाओं में विस्तृत कटौती तक पहुंच गई है। अकेले 2015–16 के केंद्रीय बजट में ही मोदी सरकार ने दलितों के लिए उप योजना में 19734 करोड़ रु. की कटौती कर दी और इसे 2014–15 के 50,548 करोड़ रु. के मुकाबले 2015–16 में घटाकर 30,850 करोड़ रु. कर दिया। अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति (अत्याचार निवारण) संशोधन अध्यादेश, 2014 में दलितों/आदिवासियों के खिलाफ विभिन्न अपराधों को शामिल करने के प्रस्ताव को मोदी सरकार ने निरस्त कर दिया।

हम इस विषय में प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी से मॉफीनामे के साथ एक विस्तृत बयान की मांग करते हैं।''

रणदीप सिंह सुरजेवाला